Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

मार्च (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- महासमुंद में पाँच संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ 3
- छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक 27वाँ भोरमदेव महोत्सव 19 एवं 20 मार्च को 3
- मुख्यमंत्री ने विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तिका 'जात्रा' का किया विमोचन 4
- मुख्यमंत्री ने संत कवि पवन दीवान के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदाय करने की घोषणा की 4
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 5
- मुख्यमंत्री ने रायपुर में गहोई भवन का किया लोकार्पण 6
- छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 6
- स्कूल शिक्षा विभाग को मिला एमबिलियंथ अवॉर्ड 8
- ग्राम सोंड्रा में मिली पांडुवंशी काल की बुद्ध प्रतिमा 8
- 'अंगना म शिक्षा'कार्यक्रम को मिला वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड 9
- अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ऑल ओवर चैंपियन 11
- मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को किया 7 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान 11
- नारको टेस्ट के लिये छत्तीसगढ़ हुआ आत्मनिर्भर, एम्स में नारको टेस्ट की मिली मंज़ूरी 12
- मंत्री परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय 13
- भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी 13
- छत्तीसगढ़ का ब्रॉड गेज नेटवर्क 100 प्रतिशत विद्युतीकृत हुआ 14
- मांझिनगढ़ को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा 14
- मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' का किया शुभारंभ 15
- विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पारित 17
- विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 पारित 18
- मुख्यमंत्री ने किया राज्य के पहले फुल हाईट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण 19
- खेल अकादमी बिलासपुर की बालिका ने जीता गोल्ड मेडल 19
- नगरी दुबराज को मिला जीआई टैग 20
- श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित 21
- महिला स्वरोज़गार और सुपोषण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में एक और मिलेट कैफे का संचालन शुरू 22
- राज्यपाल हरिचंदन ने न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाई शपथ 23
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य 23

नोट :

छत्तीसगढ़

महासमुंद में पाँच संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

28 फरवरी, 2023 को ज़िला प्रशासन महासमुंद और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में ज़िला पंचायत सभा कक्ष में 'पाँच संकल्प : कल आज और कल' महा-अभियान का कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- महासमुंद ज़िला कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने बताया कि पाँच संकल्प महा-अभियान का उद्देश्य पाँच स्वस्थ्य व्यवहारों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाना है। साथ ही हर वर्ग के लोगों के बीच स्वास्थ्य को लेकर आ रही चुनौतियों के समाधान के लिये कार्ययोजना बनाकर काम करना है, ताकि लोग बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें।
- उन्होंने बताया कि पाँच संकल्प के माध्यम से पाँच व्यवहार जिसमें स्वस्थ किशोरावस्था का संकल्प, प्रसव पूर्व जाँच व संस्थागत प्रसव का संकल्प, एनीमिया मुक्ति का संकल्प, स्तनपान को बढ़ावा देने का संकल्प, संपूर्ण पोषण विविधता का संकल्प शामिल हैं।
- कलेक्टर ने कहा कि व्यवहार परिवर्तन एक दिन की बात नहीं इसके लिये लगातार काम करने की आवश्यकता है और सभी व्यवहार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन संकल्पों से हम आईएमआर और एमएमआर में कमी ला सकते हैं।
- यूनिसेफ छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि केवल एक घंटे के अंदर माँ का दूध पीने से 22 प्रतिशत तक बच्चों की मृत्यु में कमी आ सकती हैं एवं हाथ धोने से 40% तक बीमारियों को कम किया जा सकता है, इन संकल्पों से ज़िले में परिवर्तन लाया जा सकता है।
- ज़िला पंचायत सीईओ एस.आलोक ने बताया कि पाँच संकल्प के प्रति जागरूकता के लिये विभिन्न विभागों के अब तक लगभग 60 हज़ार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है जो समाज में इन व्यवहारों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे।

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक 27वाँ भोरमदेव महोत्सव 19 एवं 20 मार्च को

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम से आयोजित होने वाले भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन आगामी 19 और 20 मार्च को किया जाएगा। यह 27वाँ भोरमदेव महोत्सव होगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक महत्त्व के स्थल भोरमदेव मंदिर की ख्याति को बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष तेरस के समय भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
- इस महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग भोरमदेव महोत्सव आयोजन समिति, ज़िला प्रशासन, भोरमदेव तीर्थ प्रबंधकारिणी समिति एवं जनसहयोग से किया जाता है।
- प्रारंभ में भोरमदेव में महाशिवरात्रि एवं चैत्र कृष्ण तेरस को दो तिथियों पर मेले का आयोजन किया जाता रहा है। सन् 1995 में अविभाजित मध्य प्रदेश में तेरस मेला को भोरमदेव महोत्सव का स्वरूप दिया गया। 1998 में कबीरधाम ज़िला गठित होने के बाद 1999 में भोरमदेव महोत्सव का पाँचवां आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ नया राज्य गठित होने के बाद 2001 में भोरमदेव महोत्सव का सातवाँ आयोजन हुआ।
- भोरमदेव छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले में कवर्धा से 18 किमी. दूर तथा राजधानी रायपुर से 125 किमी. दूर चौरागाँव में एक हज़ार वर्ष पुराना मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।

- मंदिर कृत्रिमतापूर्वक पर्वत शृंखला के बीच स्थित है, यह लगभग 7 से 11 वीं शताब्दी तक की अवधि में बनाया गया था। इस मंदिर में खजुराहो मंदिर की झलक दिखाई देती है, इसलिये इस मंदिर को 'छत्तीसगढ़ का खजुराहो'भी कहा जाता है।
- मंदिर का मुख पूर्व की ओर है। मंदिर नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण है। मंदिर में तीन ओर से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर एक पाँच फुट ऊँचे चबुतरे पर बनाया गया है। तीनों प्रवेश द्वारों से सीधे मंदिर के मंडप में प्रवेश किया जा सकता है।
- मंडप की लंबाई 60 फुट है और चौड़ाई 40 फुट है। मंडप के बीच में 4 खंबे हैं तथा किनारे की ओर 12 खंबे हैं, जिन्होंने मंडप की छत को सँभाल रखा है। सभी खंबे बहुत ही सुंदर एवं कलात्मक हैं। प्रत्येक खंबे पर कीचन बना हुआ है, जो कि छत का भार सँभाले हुए है।

मुख्यमंत्री ने विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तिका 'जात्रा' का किया विमोचन

चर्चा में क्यों ?

3 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर डॉ. सत्यजीत साहू द्वारा लिखित एवं 'जात्रा' शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सत्यजीत साहू ने बताया कि पुस्तिका में छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के संकेंद्रण, उनकी जीवनशैली, रहन-सहन और खान-पान का उल्लेख किया गया है।
- इसके साथ ही उनकी टीम के द्वारा शिविर के माध्यम से इन जनजातियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही छोटी-मोटी बीमारियों के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के लिये किये गए प्रयासों की भी जानकारी दी गई है।
- उन्होंने बताया कि उनकी टीम सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में कैंप लगाकर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवाइयाँ भी मुहैया करा रही है।

मुख्यमंत्री ने संत कवि पवन दीवान के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदाय करने की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

3 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित 'संत कवि पवन दीवान'श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह में संत कवि पवन दीवान के सम्मान में उनके नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने की महत्त्वपूर्ण घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- संत कवि पवन दीवान के नाम से यह पुरस्कार आगामी राज्य अलंकरण समारोह से प्रतिवर्ष प्रदान किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर साहित्य तथा कविता लेखन के क्षेत्र में विशिष्ठ योगदान के लिये छत्तीसगढ़ के कवि तथा साहित्यकारों को सम्मानित भी किया।
- इनमें पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे को विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान-2023 से नवाजा गया। इसी तरह अरूण कुमार निगम तथा काशीपुरी कुंदन को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से पुरस्कृत किया गया।
- प्रत्येक को पुरस्कार स्वरूप 21-21 हज़ार रुपए की राशि और शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।
- उन्होंने इस मौके पर विप्र योग पत्रिका तथा विप्र महाविद्यालय के मासिक बुलेटिन का विमोचन भी किया।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संत कवि पवन दीवान का छत्तीसगढ़ की माटी से गहरा लगाव था। उनकी कविता में बार-बार छत्तीसगढ़ के माटी का उल्लेख हुआ है। इनके लेखन में समाज के तत्कालीन दशा का बहुत ही सुंदर और सहज चित्रण मिलता है, जो हर वर्ग और हर समाज के लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती थी।
- छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले राजिम (महानदी पैरी और सोदूर नदी का जीवंत संगम) के पास स्थिति किरवई गाँव में 1 जनवरी, 1945 को प्रतिष्ठित ब्राम्हण परिवार में संत कवि पवन दीवान का जन्म हुआ था।
- वर्ष 1975 में आपातकाल के बाद सन् 1977 में वे जनता पार्टी के टिकट पर राजिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और कॉन्ग्रेस के दिग्गज नेता श्यामाचरण शुक्ल (कॉन्ग्रेस पार्टी) को हराकर सबको चौंका दिया। वे अविभाजित मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार में जेल मंत्री रहे।
- इसके बाद वे कॉन्ग्रेस के साथ आ गए और फिर पृथक् राज्य छत्तीसगढ़ बनने तक कॉन्ग्रेस में रहे। पूर्व सरकार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे।

छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

चर्चा में क्यों ?

3 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का 'आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23' पटल पर प्रस्तुत किया।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य का जी.एस.डी.पी. स्थिर भावों पर वर्ष 2021-22 में 2 लाख 67 हज़ार 6 सौ 81 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2 लाख 89 हज़ार 82 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष विकास दर आठ प्रतिशत होना अनुमानित है।
- स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 20211-12) अग्रिम अनुमान वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाज़ार मूल्य (GSDP at Market Prices) पर गत वर्ष 2021-22 की तुलना में आठ प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (कृषि पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 93 प्रतिशत वृद्धि, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में 7.83 प्रतिशत वृद्धि एवं सेवा क्षेत्र में 9.21 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- प्रचलित भावों पर अग्रिम अनुमान वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाज़ार मूल्य) (GSDP at Market Prices) पर गत वर्ष 2021-22 के रुपए 406416 करोड़ से बढ़कर 457608 करोड़ रुपए होना संभावित है, जो कि 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- इसमें वर्ष 2021-22 में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र 85492 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 94635 करोड़ रुपए इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में 163616 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 183586 करोड़ रुपए एवं सेवा क्षेत्र में 136329 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 155995 करोड़ रुपए होना संभावित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्रमश: 70, 12.21 एवं 14.43 प्रतिशत आकलित है।
- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बाज़ार मूल्य पर (GSDP at Market Prices) त्वरित अनुमान के अनुसार गत वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (कृषि, उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में 8.07 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 9.80 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

नोट :

- प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार 1,20,704 (एक लाख बी हज़ार सात सौ चार) रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-23 अग्रिम अनुमान में 1,33,898 (एक लाख तैंतीस हज़ार आठ सौ अठानबे) रुपए होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने रायपुर में गहोई भवन का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

5 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में एम्स के समीप टाटीबंध में रायपुर के श्रीगहोई वैश्य समाज द्वारा बनवाए गए नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि एम्स में मरीजों के इलाज के दौरान मरीजों और उनके परिजनों के रुकने की व्यवस्था के लिये श्रीगहोई वैश्य समाज द्वारा यह भवन बनवाया गया है।
- उन्होंने बताया कि नवनिर्मित भवन के बनने से दूसरे समाज के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों के लिये यह भवन काफी उपयोगी होगा। कई बार इलाज के लिये काफी समय के लिये रुकना पड़ता है, ऐसे में इस भवन के माध्यम से मरीजों और उनके परिजनों की रुकने की समस्या का समाधान हो सकेगा और उन्हें काफी राहत प्रदान करेगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि समाज का यह कार्य उच्चकोटि की मानव सेवा है। कोई भी समाज जिसके पास जमीन नहीं है, उन्हें सामाजिक कार्यों के लिये निर्धारित राशि देने पर भू-खंड दिया जा रहा है। कलेक्टर गाइडलाइन को भी 30 प्रतिशत कम कर दिया है।

छत्तीसगढ़ बजट 2023-24

चर्चा में क्यों?

6 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिये वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 1 लाख 21 हज़ार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह बजट मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित 'छत्तीसगढ़ मॉडल' में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मज़बूत कदम साबित होगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2023-24 के बजट की आर्थिक स्थिति :-
    - स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है।
    - वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93 प्रतिशत वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.83 प्रतिशत वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्रों में राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक अनुमानित है।
    - प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 4 लाख 06 हज़ार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4 लाख 57 हज़ार 608 करोड़ रुपए होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।
    - वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।
- बजट के मुख्य आकर्षण-
    - 'धान का कटोरा' के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को 'धन का कटोरा' बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिये 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिये भी विस्तार।
    - शिक्षित बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की नवीन योजना के अंतर्गत 2500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    - निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रुपए प्रति माह दी जाएगी।
    - नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिये 1 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान।
    - महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    - मनेंद्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम ज़िले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    - कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी। बजट में इसके लिये 25 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    - 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने के लिये 870 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    - मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिये 38 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    - नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने हेतु प्रावधान।
    - आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 6 हज़ार 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपए प्रति माह। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हज़ार 250 रुपए से बढ़ाकर 5 हज़ार रुपए प्रति माह। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हज़ार 500 रुपए से बढ़ाकर 7 हज़ार 500 रुपए प्रति माह।
    - मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रुपए प्रति माह की दर से मानदेय।
    - ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए, 3,375 रुपए को बढ़ाकर 4,500 रुपए, 4,050 को बढ़ाकर 5,500 रुपए एवं 4,500 रुपए को बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह। ग्राम पटेल का मासिक मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए।
    - मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि 1,500 रुपए को बढ़ाकर 1,800 रुपए प्रति माह। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रुपए से बढ़ाकर 2,800 रुपए प्रति माह।
    - होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रुपए से अधिकतम 6,420 रुपए प्रति माह की वृद्धि।
    - स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपए एवं अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए मासिक मानदेय।
    - पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 50 लाख।

नोट :

स्कूल शिक्षा विभाग को मिला एमबिलियंथ अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

6 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में 'निकलर ऐप' द्वारा पढ़ाई कराने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग को एमबिलियंथ पुरस्कार से नवाजा गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि साउथ एशिया में एमबिलियंथ अवॉर्ड मोबाइल के माध्यम से आम जनता तक तकनीकी का उपयोग कर जीवन सुगम बनाने की दिशा में किये जा रहे नवाचारों को सम्मानित करता है, जिसकी शुरुआत 2010 से की गई थी, सम्मान देने की यह 12वीं श्रृंखला है।
- छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग और एनआईसी ने भी शिक्षकों के आकलन संबंधी कार्य को आसान करने के लिये लंबी रिसर्च करते हुए निकलर ऐप का निर्माण किया है।
- इस टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षकों के कार्यों को आसान करने हेतु किया जाता है। ऐप के उपयोग के लिये सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर निकलर ऐप को डाउनलोड करना होता है।
- स्कूल के यू-डाइस के आधार पर पोर्टल से विद्यार्थियों के लिये क्यूआर कोड वाले कार्ड डाउनलोड कर उसे एक पुठ्ठे में चिपकाना पड़ता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये इस प्रकार से एक यूनिक कार्ड उनके नाम से देना होता है। इसे आपस में बदलना नहीं चाहिये। यह उस बच्चे के नाम से उसके पास पूरे सत्र में रहना चाहिये।
- किसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछना हो तो निकलर ऐप में उस पाठ से संबंधित उपलब्ध प्रश्न निकालकर पूछ सकते हैं या फिर स्वयं अपने प्रश्न दे सकते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न के चार विकल्प होने चाहिये। बच्चों को सही विकल्प के आधार पर कैसे कार्ड को पकड़ना है, यह सिखाना होगा।
- निकलर ऐप का उपयोग कर बच्चों की उपस्थिति भी ली जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों के ऑडियो भी बनाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐप के उपयोग में कुछ भी दिक्कत आती है तो शिक्षकों के बीच से ही तकनीकी रूप से विशेषज्ञ शिक्षक उनके हेल्प वीडियो बनाकर सहायता करते हैं, जिससे कक्षा में इसको क्रियान्वित करना आसान हो गया है।
- समग्र शिक्षा की ओर से इस ऐप के उपयोग हेतु निरंतर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष सभी स्कूलों को इंटरनेट के लिये बजट भी उपलब्ध करवाया गया है। शिक्षकों को निकलर ऐप के उपयोग के लिये प्रशिक्षित भी किया गया है।
- विदित है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 14 नवंबर, 2022 को लॉन्च किये गए सुघ्घर पढ़वैया कार्यक्रम में भी स्कूलों का आकलन निकलर ऐप के माध्यम से बहुत कम समय में किया जा सकेगा। इसके लिये भी शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है।

ग्राम सोंड्रा में मिली पांडुवंशी काल की बुद्ध प्रतिमा

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रायपुर-बिलासपुर मार्ग में स्थित ग्राम सोंड्रा में गृह निर्माण के लिये किये जा रहे उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य पुरातात्त्विक प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि ग्राम सोंड्रा में दिलेंद्र बंछोर द्वारा व्यक्तिगत आवास परिसर में गृह निर्माण हेतु किये जाने वाले उत्खनन कार्य के दौरान भूमि की सतह से लगभग 3 फीट की गहराई से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है।
- इस संबंध में जानकारी मिलते ही पुरातत्त्व विभाग की टीम (डॉ. पी.सी. पारख, डॉ. वृषोत्तम साहू तथा डॉ. राजीव मिंज) के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।
- पुरातत्त्व एवं अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर से बिलासपुर मुख्य मार्ग में 16 किमी. की दूरी पर सांकरा से 2 किमी. पश्चिम दिशा में ग्राम सोंड्रा स्थित है। उक्त स्थल से खारुन नदी लगभग 3 किमी. पश्चिम दिशा पर स्थित है। प्रतिमा प्राप्ति स्थल ग्राम के सबसे ऊंचाई वाले भाग पर स्थित है और यहाँ प्राचीन टीला होने के साक्ष्य दिखाई देते हैं।

नोट :

- अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय बलुआ पत्थर में निर्मित इस प्रतिमा की चौड़ाई 74X ऊँचाई 87X मोटाई 40 सेंटीमीटर है।
- बुद्ध की इस विशाल प्रस्तर प्रतिमा के माथे पर ऊर्णा (तिलक चिह्न) का अंकन इसे अनोखा रूप प्रदान करती है और इस आधार पर इसके ध्यानी बुद्ध होने की संभावना अधिक प्रतीत होती है। बुद्ध की यह आवक्ष प्रतिमा अपूर्ण है, जिस पर छेनी के चिह्न साफ दिखाई दे रहे हैं।
- त्रि-स्तरीय निर्माण तकनीक में बनी बुद्ध प्रतिमा का यह ऊपरी भाग है। इस तकनीक का प्रयोग बलुआ पत्थर की विशाल प्रतिमाओं के निर्माण हेतु किया जाता था, जिसमें किसी प्रतिमा को तीन प्रस्तर खंडों में योजना के अनुरूप स्तरों में निर्मित कर लंबवत स्थापित किया जाता था। इस तकनीक की बनी बुद्ध प्रतिमा के उदाहरण छत्तीसगढ़ के सिरपुर व राजिम और बिहार के बोधगया में देखे जा सकते हैं।
- अधिकारियों ने बताया कि स्थल निरीक्षण करने पर यहाँ अन्य प्रतिमाओं के होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि निकट ही में स्थित मंदिर में तथा मंदिर के बगल में बने चबूतरे पर स्थापित हैं।
- प्रतिमाओं में भूमिस्पर्श मुद्रा में बुद्ध, उपासक, अज्ञात स्थानक प्रतिमा, योगिक ध्यानी मुद्रा में बुद्ध, ललितासन मुद्रा तारा, स्थानक बोधिसत्त्व के साथ ही 4 शिवलिंग, 4 खंडित पायदार सिलबट्टे, 1 प्रणाल युक्त प्रतिमा पीठ, कुछ खंडित प्रतिमाएँ व स्थापत्य खंड प्राप्त हुए हैं। उक्त स्थल का पुरावशेष पांडुवंशी काल का (6वीं से 9वीं शताब्दी ई.) प्रतीत हो रहा है।

'अंगना म शिक्षा' कार्यक्रम को मिला वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड

चर्चा में क्यों?

13 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को एक बार पुन: अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिये राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित 'अंगना म शिक्षा' कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 में किये गए कार्य के लिये स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- 'अंगना म शिक्षा' का यह पूरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष इस कार्यक्रम का तीसरा वर्ष होगा और प्रतिवर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिजाइन शामिल किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो ऐसे लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिये अतिरिक्त प्रयास करते हैं।
- इस अवार्ड को वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। यह अवार्ड डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों के लिये प्रदान किया जाता है।
- विदित है कि कोरोना के समय जब स्कूल शिक्षा विभाग का पूरा अमला बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिये निरंतर प्रयासरत था और शिक्षकों को इस कार्य के लिये प्रोत्साहित करते हुए नए-नए तरीकों से बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने की कोशिश की जा रही थी, उसी समय राज्य के कुछ महिला शिक्षिकाओं ने इस राज्यव्यापी कार्यक्रम 'पढ़ई तुंहर दुआर' में अपने योगदान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने माताओं को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से घर पर रहते हुए ही बच्चों को सिखाने के प्रयास को 'अंगना म शिक्षा' के रूप में प्रारंभ किया।

- 'अंगना म शिक्षा'कार्यक्रम के माध्यम से माताओं में अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति अलख जगाने में सफलता पाई। माताओं एवं छोटे बच्चों को गाँव-गाँव में मेलों का आयोजन कर, मेले में माताओं एवं बच्चों को आमंत्रित कर घर में उपलब्ध सामग्री जैसे बर्तन, सब्जी, फल, कपड़े आदि का उपयोग कर सिखाया जाए, इस पर कार्य किया गया।
- इस कार्यक्रम में ग्राम स्तर पर बेहतर कार्य कर रही माताओं को स्मार्ट माता के रूप में चयन कर सम्मानित किया गया।
- स्मार्ट माता अन्य माताओं को भी इस कार्यक्रम में जोड़े रखने एवं सीखने में सहयोग के साथ-साथ समय-समय पर बालवाड़ी एवं प्राथमिक शालाओं में जाकर बच्चों की शिक्षा में सहयोग एवं शिक्षकों से अपने बच्चों के सीखने के कार्य संबंधी जानकारी लेने का कार्य भी करती थीं। इस कार्यक्रम के माध्यम से माताओं में बच्चों को घर पर पढ़ाने की संस्कृति विकसित करने में सफलता मिली है।
- बच्चों ने जो कुछ सीखा, उसे रिपोर्ट कार्ड के बदले एक सपोर्ट कार्ड डिजाइन कर माताओं के हस्ताक्षर से माताओं द्वारा अपने बच्चों के शिक्षकों को देना सुनिश्चित किया गया। माताओं को बहुत आसान तरीकों से सरल चिन्हों का उपयोग कर बच्चों की विभिन्न दक्षताओं में स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया।
- शिक्षिकाओं के समूहों द्वारा संकुल, विकासखंड, ज़िले एवं राज्य स्तर पर कोर ग्रुप के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की मानिटरिंग की व्यवस्था की गई।

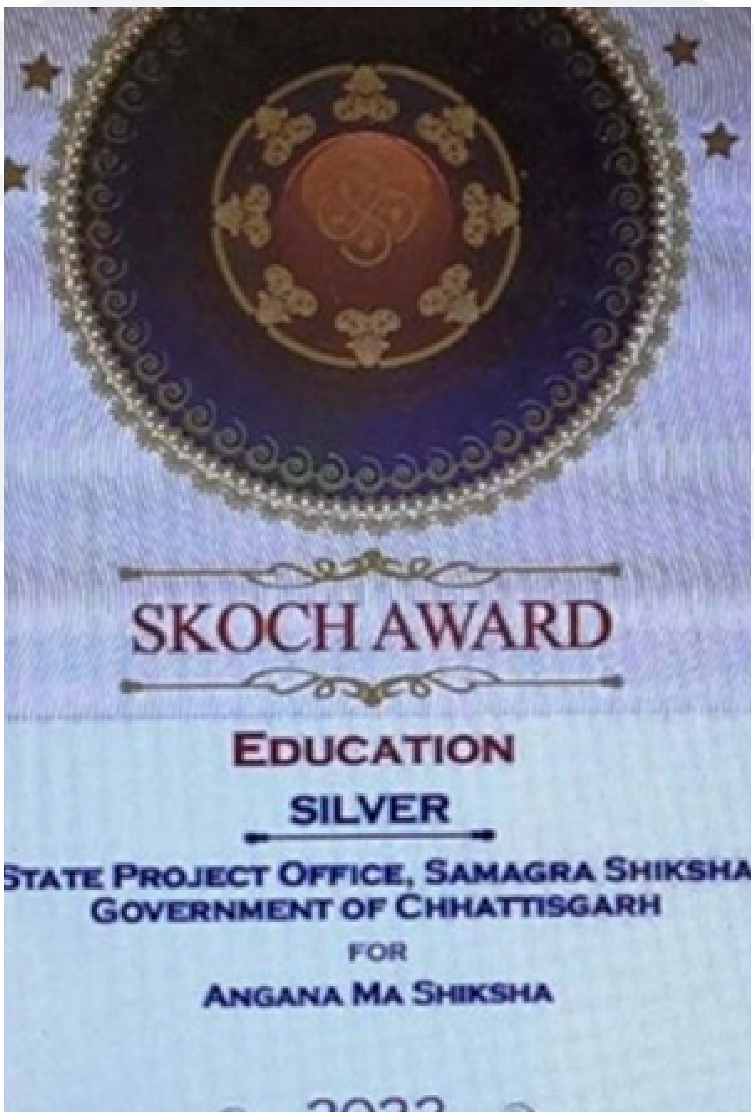

अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ऑल ओवर चैंपियन

चर्चा में क्यों ?

14 मार्च, 2023 को हरियाणा के पंचकूला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवर ऑल चैंपियन बना।

प्रमुख बिंदु

- 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कर्नाटक को पछाड़ते हुए पुन: अपना प्रथम स्थान कायम रखा।
- गौरतलब है कि पाँच दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, कैरम, चेस, वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी, जैसे- इंडोर गेम के साथ-साथ क्रिकेट, फुटबॉल, बॉस्केट बॉल, हॉकी, गोल्फ, एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट होते हैं।
- इस प्रतियोगिता में वन विभाग के उच्चतम अधिकारी पीसीसीएफ से लेकर गार्ड तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेते हैं।
- 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के वन विभाग टीम ने क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर को हराकर सातवीं बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी तरह फुटबॉल में हरियाणा के टीम को हराकर छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ की बॉस्केट बॉल टीम ने कर्नाटक की टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया।
- छत्तीसगढ़ ने वेटलिफ्टिंग, पॉवरलिफ्टिंग में कुल 19 स्वर्ण, टेनिस में 12 स्वर्ण, बैडमिंटन में 04 स्वर्ण, तैराकी में 06 स्वर्ण, एथलेटिक्स में 18 स्वर्ण, 10 रजत, 08 काँस्य पदक जीते हैं। इसी प्रकार टेनिस में 09 स्वर्ण और 02 रजत पदक प्राप्त किया है।
- इस तरह इस वर्ष की 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीतकर कुल 542 अंक प्राप्त किये।

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को किया 7 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान

चर्चा में क्यों ?

15 मार्च, 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री द्वारा किये गए भुगतान में 16 फरवरी से 28 फरवरी तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किये गए 13 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 25 लाख रुपए, गौठान समितियों को 1.65 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 1.14 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल हैं।
- 16 फरवरी से 28 फरवरी तक गौठानों में कुल 13 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है, जिसके एवज में गोबर विक्रेताओं को अंतरित की जाने वाली 4.25 करोड़ रुपए की राशि में से 1.92 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 2.33 करोड़ रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया जाएगा।
- स्वावलंबी गौठानों द्वारा गोबर खरीदी के एवज में अब तक 52 करोड़ रुपए का भुगतान स्वयं की राशि से किया गया है।
- गौरतलब है कि 'गोधन न्याय योजना' के तहत राज्य में हितग्राहियों को आज भुगतान की गई राशि को मिलाकर अब तक 419 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
- गोबर विक्रेताओं से क्रय किये गए गोबर के एवज में 215 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 185 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई, 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 28 फरवरी, 2023 तक गौठानों में 75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बड़ी संख्या में गौठान स्वावलंबी हो रहे हैं। स्वावलंबी गौठानों को प्रोत्साहित करने के लिये गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष और सदस्य को मानदेय प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- उन्होंने कहा कि अब गोबर से अन्य उत्पादों के बनाने के अलावा बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है। बस्तर के डोमरपाल में गोबर से बिजली बनाने के संयंत्र को ग्रिड से सिंक्रोनाईज किया जा चुका है। इससे बनने वाली बिजली की दर 9 रुपए प्रति यूनिट तय कर दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठान न सिर्फ अपनी सहभागिता निभा रहे हैं बल्कि निरंतर बढ़त बनाए हुए हैं। बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रही है।
- वर्तमान में 50 फीसदी से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान की अन्य गतिविधियों को स्वयं की राशि से पूरा कर रहे हैं।

नारको टेस्ट के लिये छत्तीसगढ़ हुआ आत्मनिर्भर, एम्स में नारको टेस्ट की मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों?

15 मार्च, 2023 को प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में जानकारी दी कि नारको टेस्ट के लिये छत्तीसगढ़ अब आत्मनिर्भर बन गया है। रायपुर एम्स में नारको टेस्ट की मंजूरी मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

- गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में बताया कि अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किये जाने वाले नारको टेस्ट के लिये देश के बड़े राज्यों में नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने नारको टेस्ट के लिये ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं और रायपुर एम्स के साथ मिलकर इसके लिये ज़रूरी मशीनें भी मंगा ली गई हैं।
- गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने के लिये लगातार नयी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है।
- बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिये सभी पाँच रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जा रही है। अपराधों पर लगाम लगे इसके लिये दुर्ग में फारेंसिंक साइंस लेबोरेट्री कालेज की स्थापना भी की जाएगी।
- वर्तमान में प्रदेश के 11 ज़िलों में डायल 112 की सुविधा थी जिसमें अब 17 अन्य ज़िलों को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह से अब डायल 112 की सुविधा 28 ज़िलों में होगी।

नोट :

मंत्री परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यो ?

17 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्री परिषद की बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये करीब 2500 करोड़ रुपए की विश्व बैंक परियोजना- चाक के क्रियान्वयन के लिये शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।
- बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल प्राप्त कु. आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थायी रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।

भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

17 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत दस नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार ये केंद्र अलग-अलग ज़िलों में एक-एक खेल के लिये खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 24 हो गई है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी, कुश्ती, फुटबाल, कबड्डी और तीरंदाजी के लिये खेलो इंडिया लघु केंद्र की मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों की स्थापना के लिये भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग संचालनालय ने विभिन्न खेलों की खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा था, जिसमें बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा में फुटबॉल, बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली में फुटबॉल तथा सूरजपुर में फुटबॉल खेल की नए खेलो इंडिया लघु केंद्र स्वीकृत किये गए हैं।
- इससे पहले ज़िला नारायणपुर में मलखंभ, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वालीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर में हॉकी एवं राजनांदगाँव में हॉकी की खेलो इंडिया लघु केंद्र खोलने की कार्यवाही प्रगति पर है।
- अब तक पहले चरण के 7 ज़िलों में से प्रत्येक ज़िले को लघु केंद्र हेतु 7-7 लाख रुपए जारी किये जा चुके हैं। अन्य 7 स्वीकृत ज़िले बालोद में वेटलिफ्टिंग, बलौदाबाज़ार में फुटबॉल, दुर्ग में कबड्डी, कांकेर में खो-खो, रायपुर में वेटलिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन एवं सुकमा में फुटबॉल के लघु केंद्रों हेतु राशि भारतीय खेल प्राधिकारण द्वारा दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

नोट :

- इस प्रकार राज्य के 24 ज़िलों में 24 खेलो इंडिया लघु केंद्र के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। प्रत्येक खेल के स्थानीय सीनियर खिलाड़ियों को सेंटर से जोड़ा जाएगा, उन्हें प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिये मानदेय भी दी जाएगी।
- सभी खेलो इंडिया सेंटर्स में बालक एवं बालिका खिलाड़ियों का बराबर प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित की जाएगी। इन सेंटर्स को भारतीय खेल प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ का ब्रॉड गेज नेटवर्क 100 प्रतिशत विद्युतीकृत हुआ

चर्चा में क्यों ?

18 मार्च, 2023 को भारत सरकार के प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर यानी शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य हासिल करने के क्रम में भारतीय रेल ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज के मौजूदा नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- 1,170 किमी. रूट के विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप लाइन हॉल लागत घटने (लगभग 5 गुनी कम), भारी हॉलेज क्षमता, सेक्शनल क्षमता बढ़ने, इलेक्ट्रिक लोको की परिचालन और रखरखाव लागत घटने, ऊर्जा दक्षता और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटने व पर्यावरण अनुकूल परिवहन माध्यम बनने से विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है।
- इसके अलावा, रेलवे की 100 प्रतिशत विद्युतीकृत नेटवर्क की नीति के क्रम में अब विद्युतीकरण के साथ ही नए ब्रॉड गेज नेटवर्क को मंजूरी दी जाएगी।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र साउथ ईस्ट सेंट्रल और ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और कोरबा आदि छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं।
- बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और मुंबई-हावड़ा मुख्य लाइन पर स्थित है। यह एक महत्त्वपूर्ण जंक्शन है और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में देश में सबसे अधिक माल ढुलाई होती है और यहाँ से रेलवे को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। रेल नेटवर्क छत्तीसगढ़ से देश के अन्य हिस्सों में खनिजों, कृषि उत्पादों और अन्य सामानों के परिवहन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ प्रतिष्ठित ट्रेनें हैं: दुर्ग-जगदलपुर एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। ये ट्रेनें राज्य के विभिन्न हिस्सों और भारत के अन्य प्रमुख शहरों के लिये सुविधाजनक संपर्क प्रदान करती हैं।

मांझिनगढ़ को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

18 मार्च, 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागाँव ज़िला के केशकाल विधानसभा के ग्राम बाँसकोट में भक्त माता कर्मा जयंती तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होते हुए मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में बांसकोट में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा की स्थापना, उप स्वास्थ्य केंद्र गम्हरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने, बाँसकोट में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने तथा ज़िले के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये केशकाल में इंडोर स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की।
- विदित है कि कोंडागाँव ज़िले के केशकाल के बड़ेराजपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत खल्लारी से 8 किमी. ऊपर की ओर पहाड़ों में बसा मांझिनगढ़ समुद्री तल से 5000 फीट ऊपर है। यहाँ से कांकेर, सरोना और दुधावा बांध भी देखा जा सकता है।
- मांझिनगढ़ चट्टानों के बीच गुफा है जहाँ हज़ारों वर्ष पुराना शैल चित्र है। मांझिनगढ़ को आदिमानव की स्थली माना जाता है और स्थानीय बड़े बुजुर्गों द्वारा एलियन जैसे आश्चर्यजनक बौने प्रजाति के 'उइका' लोगों का राज होने का बहुत ही रोचक किवदंती कहानी बताई जाती है।

नोट :

- मांझिनगढ़ कोंडागाँव ज़िले के एक विशेष प्रचलित होते ईको टूरिज्म स्थल के रूप में लोगों को लुभा रहा है। यहाँ के घने जंगल, वन्य जीव, औषधीय पौधे, प्रागैतिहासिक चित्रकला, सुंदर मनमोहक वादियाँ तथा भौगोलिक संरचनाएँ पर्यटकों को एक विशेष अनुभव प्रदान करती हैं।
- मांझिनगढ़ में माता गढ़मावली वास करती हैं। भादो महीने में केशकाल के भंगाराम जातरा के दिन ही इस स्थान पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। अपने गाँव को और गाँव वालों को दैविक आपदा से बचाए रखने और सुख, शांति समृद्धि की कामना को सँजोए रखने वाले जातरा का स्थानीय लोगों के लिये बहुत विशिष्ट महत्त्व होता है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

21 मार्च, 2023 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष से राज्य के सभी 33 ज़िलों के 42 स्थानों में राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर वन संसाधन अधिकारों को लोगों तक सुगमता से पहुँचाने के लिये मोबाईल आधारित एफआरए टूल का लोकार्पण किया और वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने तथा व्यापारियों की सुविधा के लिये छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) का शुभारंभ किया।
- साथ ही उन्होंने शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1458 हितग्राहियों के खाते में कुल 22 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना देश में एक अनूठी योजना है, जिसमें वाणिज्यिक प्रजातियों का वृक्षारोपण कर निजी व्यक्ति, संस्था अथवा कंपनियों के माध्यम से अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं। यह केवल वृक्षारोपण की योजना न होकर देश के जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी हमारी सहभागिता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'में सभी वर्ग के इच्छुक किसानों की पड़त भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण होगा। योजना के तहत 33 ज़िलों के 23 हज़ार 600 किसानों द्वारा 36 हज़ार 230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा। योजना से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50 हज़ार रूपए तक की आय होगी। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय होगी।

- वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा की दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य है। 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1 लाख 80 हज़ार एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा।
- यह योजना हितग्राहियों की आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण योजना है। योजना में 5 एकड़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को शत-प्रतिशत अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
- 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' का लाभ किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएँ, निजी शिक्षण संस्थाएँ, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक उठा सकते हैं।
- छत्तीसगढ़ में योजना के तहत इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के वृक्ष का रोपण किया जाएगा। इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बाँस, टिश्यू कल्चर बंबू, रक्त चंदन, आँवला, खमार, शीशम तथा महानीम आदि के पौधे रोपे जाएंगे।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जारी करने की प्रक्रिया को ट्रेक करने हेतु मोबाइल एप का लोकार्पण भी किया।
  - इस मोबाइल एप के उपयोग से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी।
  - सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के आवेदन से लेकर अधिकार प्राप्ति तक 12 स्तर की प्रक्रिया है तथा 18 प्रपत्रों में जानकारी भरी जाती है।
  - मोबाइल एप के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का मॉनिटरिंग भी की जा सकती है।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वन विभाग द्वारा वनोपज के परिवहन हेतु तैयार कराए गए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) को लॉन्च किया।
  - इस सुविधा के अंतर्गत आवेदक ट्रांजिट परमिट के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा वन विभाग ऑनलाईन ट्रांजिट परमिट जारी करेगा। अंतर्राज्यीय सीमा में नये टी.पी. की आवश्यकता नहीं होगी।
  - मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ एनटीपीएस योजना को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कवर्धा ज़िले के सकरी नदी को संरक्षित करने तथा नदी का बहाव अपने पूर्ण क्षमता पर लाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण के माध्यम से सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम की शुरूआत की।
  - इसके तहत वन एवं राजस्व भूमि में नदी तट वृक्षारोपण कार्य, निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, वन क्षेत्रों में नरवा योजना के अंतर्गत कैंपा मद से जल एवं मृदा संरक्षण कार्य तथा राजस्व क्षेत्र में मनरेगा अंतर्गत रोपण एवं संरचानाओं का निर्माण किया जाएगा।
  - इस एकीकृत परियोजना से कर्वधा ज़िले में किसानों को घरेलू उपयोग तथा कृषि के लिये सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध होगी।

नोट :

विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पारित

चर्चा में क्यों?

22 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 प्रस्तुत और पारित हुआ। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है, जहाँ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 17 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया था।

नोट :

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बताया कि जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों या पोर्टल के हों, जो ऑफिस में काम करते हैं और वे भी जो गाँव में काम करते हैं, ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके।
- जिनके पास अधिमान्यता पत्र नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन करने का, अगर प्रेस कहता है कि वे हमारे साथ हैं और जो लगातार छह महीने के अंदर उसमें तीन लेख लिखे हों या उनकी स्टोरी छपी हो, ऐसे लोगों को भी छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है।
- यदि कोई शासकीय कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनकी शिकायत के लिये अधिकार संपन्न समिति बनाया गया है। यह समिति प्रदेश स्तर की होगी, जिसमें पत्रकार, अधिकारीगण होंगे, छह लोगों की समिति बनेगी, जो सुनवाई करेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेगी और दंड का भी प्रावधान किया गया है।
- यदि कोई समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपील का भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उसके लिये दंड का प्रावधान भी रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अफताब आलम की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनी थी, जिसके सदस्य न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंजना प्रकाश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजूराम चंद्रन, वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय ललित सुरजन, प्रकाश दुबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार रूचिर गर्ग, महाधिवक्ता, विधि विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य थे।
- इस समिति ने राज्य और दिल्ली में अनेक बैठकें करके विभिन्न संगठनों से चर्चा के बाद इसका प्रारूप बनाया और उसके बाद इस प्रारूप को विभाग को सौंपा गया, विभाग द्वारा लंबा विचार-विमर्श करके इसको विधेयक का रूप दिया गया।
- राज्यपाल से अनुमति लेकर इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और विधानसभा में यह विधेयक पारित हुआ। ऐसा विधेयक जो मूल विधेयक है और जो पहली बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, विपक्ष को भी इसमें अपनी राय रखनी थी। हालाँकि सर्वानुमति से इस विधेयक को पारित किया गया।

विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 पारित

चर्चा में क्यों ?

23 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विनियोग विधेयक-2023 पारित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी वर्ष 2018 में 03 लाख 27 हज़ार 106 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़कर 05 लाख 09 हज़ार 43 करोड़ रुपए अनुमानित है। मार्च 2020 से निरंतर 02 वर्ष तक कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियाँ मंद होने के बावजूद राज्य शासन की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था के आकार में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि वर्ष 2022-23 में 8 प्रतिशत अनुमानित है, जो अखिल भारतीय जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक तथा स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानित विकास दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है।
- कृषि क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 5.93 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 3.50 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 7.83 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 4.10 प्रतिशत है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 9.21 प्रतिशत और राष्ट्रीय वृद्धि दर 9.10 प्रतिशत रही।
- राज्य के स्वयं के करों का राजस्व वर्ष 2018-19 में 21 हज़ार 427 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 38 हज़ार करोड़ रुपए अनुमानित (77 प्रतिशत वृद्धि) है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा भी की।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अप्रैल से आवासहीनों, उज्ज्वला गैस योजना और शौचालय के हितग्राहियों का सर्वे कराया जाएगा। आवास योजना में जितने भी पात्र हितग्राही होंगे, उन्हें क्रमबद्ध रूप से आवास दिया जाएगा।
- वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय रु. 08 हज़ार 903 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2023-24 हेतु 18 हज़ार 660 करोड़ रुपए अनुमानित (2 गुणा से अधिक वृद्धि) है।
- राज्य सरकार ने इस वर्ष बाज़ार से कोई ऋण नहीं लिया है। गत वर्ष 2021-22 में भी राज्य द्वारा मात्र 865 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया गया था। वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ का ऋणभार जीएसडीपी का 17.9 प्रतिशत, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत से बहुत कम है।
- वर्ष 2023-24 छत्तीसगढ़ द्वारा ऋणों के ब्याज भुगतान पर राजस्व प्राप्तियों का 6.5 प्रतिशत, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से बहुत कम है।

मुख्यमंत्री ने किया राज्य के पहले फुल हाईट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

24 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर-विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रासिंग पर निर्मित राज्य के पहले फुल हाईट फोरलेन रेलवे अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग पर लोकार्पित ये राज्य का पहला फुल हाईट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज है जिसे 28.11 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
- इस फुल हाइट फोरलेन रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण से रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा।
- रायपुर से बिलासपुर मार्ग रायपुर-विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रासिंग में रेल गुजरने के कारणे बार-बार रेलवे फाटक बंद होता था और आवागमन अवरुद्ध हो जाता था। जन आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के इस महत्त्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2017 में प्रदान की गई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई 336.96 मीटर है।

खेल अकादमी बिलासपुर की बालिका ने जीता गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों?

26 मार्च, 2023 को खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण एवं प्रदेश आरचरी एसोसिएशन द्वारा ज़िला रायपुर में महिलाओं के लिये आयोजित दस का दम तीरंदाज़ी प्रतियोगिता में खेल अकादमी बिलासपुर की तुलेश्वरी खुसरो ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दस का दम तीरंदाज़ी प्रतियोगिता में बिलासपुर के ग्राम शिवतराई में संचालित तीरंदाज़ी प्रशिक्षण उपकेंद्र की खिलाड़ी कु. तुलेश्वरी खुसरो ने इंडियन राउंड में 656 अंक प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा संचालित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र (खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) बिलासपुर की खिलाड़ी कु. दिव्या यादव ने 647 अंक प्राप्त करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- विदित है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश में निरंतर खेलों को बढ़ावा दे रहा है, जिस हेतु विभाग द्वारा राज्य में खेल अकादमी प्रारंभ की जा रही हैं, जहाँ खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर की सुविधाओं के साथ गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं।
- भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्व. बी. आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत हॉकी अकादमी जून 2022 एवं तीरंदाज़ी व एथलेटिक अकादमी नवंबर 2022 से प्रारंभ हुई।
- इन अकादमियों में खिलाड़ियों को नि:शुल्क आवासीय व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे एक वर्ष से भी कम समय में खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित किये हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिये भी क्वालीफाई किया है।
- इनमें अमित कुमार ने 33वीं वेस्ट ज़ोन एथलेटिक चैंपियनशिप रायपुर, वॉक रेस 10 किमी. में स्वर्ण पदक, अंकित अहलावत ने राष्ट्रीय इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट, आंध्र प्रदेश, डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक, अर्जुन कोवाची ने तीसरी एकलव्य आवासीय विद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स मीट, आंध्र प्रदेश, 1500 मी. रेस में स्वर्ण पदक, गितेश यादव ने चौथी खेलो इंडिया ईस्ट ज़ोन आरचरी चैंपियनशिप, कोलकाता, इंडियन राउंड में रजत पदक और अमित कुमार ने राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप, बंगलूरू, वॉक रेस में कांस्य पदक के साथ एशियन चैंपियनशिप हेतु क्वालीफाई किया तथा आदित्य कुमार जूनियर इंडिया कैंप हेतु चयनित हुआ।
- राज्य शासन द्वारा ग्राम शिवतराई, ज़िला बिलासपुर में तीरंदाज़ी प्रशिक्षण उपकेंद्र स्वीकृत किया गया है, जिसे खेलो इंडिया लघु केंद्र के रूप में भी चिह्नित किया गया है। प्रशिक्षण उपकेंद्र प्रारंभ होने से खिलाड़ियों को डाईटमनी के साथ ही इंडियन एवं रिकर्व बो प्रदाय कर नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- अकादमी प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित किया है। इनमें कुबेर सिंह जगत ने चौथी खेलो इंडिया ईस्ट ज़ोन आरचरी चैंपियनशिप, कोलकाता, इंडियन राउंड में स्वर्ण पदक तथा विकास कुमार, अजय कुमार एवं कुबेर सिंह जगत ने 42वीं एन.टी.पी.सी. जूनियर नेशनल आरचरी चैंपियनशिप गोवा, इंडियन राउंड में रजत पदक जीता।

नगरी दुबराज को मिला जीआई टैग

चर्चा में क्यों ?

26 मार्च, 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामलों के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि छत्तीसगढ़ के धमतरी विकासखंड के नगरी के धान की 'नगरी दुबराज' किस्म को जीआई टैग मिला है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मध्य प्रदेश के रीवा में पाए जाने वाले सुंदरजा आम और मुरैना में बनने वाली गजक को भी जीआई टैग मिला है।
- उल्लेखनीय है कि 'नगरी दुबराज' छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग, यानी जीआई टैग मिला है। इसके पहले जीरा फूल धान की किस्म के लिये प्रदेश को जीआई टैग मिल चुका है।
- विदित है कि 29 नवंबर, 2021 को ग्वालियर में आयोजित जियोग्राफिकल इंडिकेशन कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के धमतरी के 'नगरी दुबराज' किस्म को जीआई टैग देने के लिये अनुमोदन किया गया था।
- चेन्नई द्वारा गठित कमेटी में भारत के 10 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जाँचा और परखा गया तथा नगरी दुबराज की नगरी में उत्पत्ति होने का प्रमाण स्वीकार कर लिया गया।
- ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2021 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने जीआई टैग के लिये नगरी दुबराज का प्रस्ताव भेजा था।

- नगरी दुबराज को छत्तीसगढ़ में बासमती भी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोज कार्यक्रमों में सुगंधित चावल के रूप में इस चावल का प्रयोग किया जाता है।
- नगरी दुबराज की उत्पत्ति सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी गई है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। विभिन्न शोध पत्रों में भी दुबराज का स्रोत नगरी सिहावा को ही बताया गया है।
- नगरी दुबराज से निकलने वाला चावल बहुत ही सुगंधित होता है। यह पूर्णरूप से देशी किस्म है और इसके दाने छोटे हैं। इसका चावल पकने के बाद खाने में बेहद नरम है। एक एकड़ में अधिकतम छह क्विंटल तक उपज मिलती है। धान की ऊँचाई कम और 125 दिन में पकने की अवधि है।
- वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गनाइज़ेशन (विपो) के अनुसार जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है, जिसमें किसी खास फसल, प्राकृतिक या कृत्रिम उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह बौद्धिक संपदा का अधिकार माना जाता है
- उल्लेखनीय है कि भारतीय संसद ने सन् 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 'जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स' लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य, व्यक्ति या संगठन इत्यादि को दे दिया जाता है।

श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित

चर्चा में क्यों?

28 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिये एक अप्रैल 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक के लिये न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- ये दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिये प्रतिदिन 20 रुपए और प्रतिमाह 260 रुपए की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये 225 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

नोट :

- इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये प्रति एक हज़ार अगरबत्ती के लिये 5 रुपए 85 पैसे की वृद्धि की गई है।
- न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक ज़ोन 'अ'के लिये 10 हज़ार 480 रुपए, ज़ोन 'ब' के लिये 10 हज़ार 200 रुपए और ज़ोन 'स' के लिये 9 हज़ार 960 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।
- इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को ज़ोन 'अ' के लिये 11 हज़ार 130 रुपए, ज़ोन 'ब' के लिये 10 हज़ार 870 रुपए और 'स' के लिये 10 हज़ार 610 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा।
- कुशल श्रमिकों को ज़ोन 'अ' के लिये 11 हज़ार 910 रुपए, ज़ोन 'ब'के लिये 11 हज़ार 650 रुपए और ज़ोन 'स'के लिये 11 हज़ार 390 रुपए न्यूनतम वेतन देय होगा।
- उच्च कुशल श्रमिकों को ज़ोन 'अ' के लिये 12 हज़ार 990 रुपए, 'ब' के लिये 12 हज़ार 430 रुपए और ज़ोन 'स' के लिये 12 हज़ार 170 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।
- कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिये 8 हज़ार 400 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिये अगरबत्ती रोलर्स में एक हज़ार अगरबत्ती बनाने पर 32 रुपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रुपए 51 पैसे देय होगा।

महिला स्वरोज़गार और सुपोषण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में एक और मिलेट कैफे का संचालन शुरू

चर्चा में क्यों ?

27 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िला मुख्यालय में राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने प्रदेश में महिला स्वरोज़गार, उद्यमिता सहित सुपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिलेट कैफे का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मिलेट्स के उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में मिलेट कैफे का संचालन शुरू किया गया है। इन मिलेट्स कैफे को संचालन के लिये महिला समूहों को दिया जा रहा है।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है, जो समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी कर रहा है।
- उल्लेखनीय है कि रायगढ़ ज़िले में ज़िला प्रशासन के सहयोग से मई 2022 में प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत की गई। इसका संचालन महिला समूह द्वारा किया जा रहा है। इसके खुलने के महज कुछ महीनों में ही यहाँ की मासिक आमदनी 3 लाख रुपए को पार कर गई है।
- रायगढ़ के बाद कोरबा ज़िले में मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में बालोद में अब ज़िले के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत की गई है।
- इस कैफे में पौष्टिकता से भरपूर मिलेट्स के व्यंजनों का स्वाद लोग ले सकेंगे। इस कैफे में कोदो, कुटकी, रागी तथा अन्य लघु धान्य फसलों से निर्मित विविध व्यंजन-इडली, डोसा, पोहा, उपमा, भजिया, खीर, हलवा, कुकीज आदि आम जनता के लिये उपलब्ध रहेंगे।

राज्यपाल हरिचंदन ने न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाई शपथ

चर्चा में क्यों ?

29 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन के दरबार हॉल में न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। इसके पूर्व रमेश सिन्हा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे।
- विदित है कि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लिया, जो 10 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे।
- न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद 10 मार्च को न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- बिलासपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले रमेश सिन्हा ने साल 1990 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है। साल 2011 में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया।
- उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किया गया है।
- हालाँकि वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण कोलेजियम व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, जिसका वर्तमान स्वरूप 'थर्ड जजेस केस 1998' में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से विकसित हुआ है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य

चर्चा में क्यों ?

30 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8193 सड़कें जिनकी लंबाई 40,234 किमी. है, का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के नवीनीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से बजट उपलब्ध कराने से मिली है।

- मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य शासन से इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण के लिये सर्वाधिक 700 करोड़ रुपए का बजट मिला। वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 6000 किमी. सड़कों के नवीनीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 5436 किमी. के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- प्रदेश के अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संभाग की अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 231 किमी. लंबी 75 सड़कों का 37 करोड़ रुपए की लागत से संधारण किया गया।
- इसी तरह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा संभाग की 146 सड़कें, जिनकी लंबाई 560 किमी. है, उनका संधारण 90 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। अति नक्सल प्रभावित नारायणपुर ज़िला अंतर्गत जहाँ पूर्व में कोई भी नवीनीकरण का कार्य नहीं हुआ था, वहाँ भी सड़क निर्माण पश्चात् पहली बार 10.50 किमी. लंबी 04 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनकरण कार्य हेतु 2915 किमी. लंबी 782 सड़कों के संधारण के लिये 779 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है।
- उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों में नवीनीकरण कार्य हेतु नियमित रूप से राज्य शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप नवीनीकरण कार्य में देश में अग्रणी स्थान पर है।
- पंचायत मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का संधारण एवं रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का रहता है। भारत सरकार द्वारा इसके लिये कोई भी राशि नही दी जाती है। इस संबंध में भारत सरकार को भी केंद्रांश दिये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है।
- प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8193 सड़कें जिनकी लंबाई 40,234 किमी. है, का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन निर्मित सड़कों से 10,590 पात्र बसाहटें लाभान्वित हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के लिये आवागमन का एक मात्र बारहमासी मार्ग होता है। ग्रामीणों के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जीवन रेखा के समान हैं।
- पंचायत मंत्री ने बताया कि कार्य पूर्णता पश्चात् 05 वर्ष तक नियमित संधारण कार्य का दायित्व अनुबंधकर्त्ता ठेकेदार का होता है। कुल निर्मित सड़कों में से 3664 सड़कें जिनकी लंबाई 17,577 किमी. है, पाँच वर्ष नियमित संधारण के अंतर्गत हैं, शेष सड़कों के निर्माण की पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात व नवीनीकरण की स्थिति में हैं। अब तक कुल 5609 सड़कें जिनकी लंबाई 22,700 किमी. है, का नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।